RNI No#MPBIL/2013/49052

INVESTMENT AVENUES®
इन्वेस्टमेंट ऐवेन्यूस

भोपाल, शनिवार 19 से 25 जुलाई 2025 | भोपाल, मध्यप्रदेश से प्रकाशित | वर्ष- 12 | अंक-49 | पृष्ठ- 8 | मूल्य- रु. 5 /-

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का विदेशी निवेश दौरा रहा ऐतिहासिक और सफल

भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा संयुक्त अरब अमीरात (दुबई) और स्पेन का किया गया विदेशी दौरा मध्यप्रदेश को वैश्विक निवेश नक्शे पर लाने की दिशा में एक ऐतिहासिक और सफल कदम साबित हुआ। यह दौरा न केवल राज्य में उद्योगों की संभावनाओं को व्यापक स्तर पर प्रस्तुत करने में सफल रहा, बल्कि कई प्रमुख निवेश प्रस्तावों के द्वार भी खोल गया।

मुख्यमंत्री ने दुबई में आयोजित "एमपी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डायलॉग 2025" में भाग लेते हुए प्रदेश की नई औद्योगिक नीतियों को अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया। इस आयोजन में 18 से अधिक औद्योगिक नीतियों को साझा किया गया, जिनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल, टेक्सटाइल, रिन्यूएबल एनर्जी, डेटा सेंटर, फार्मा और लॉजिस्टिक जैसे क्षेत्र शामिल हैं। डॉ. यादव ने निवेशकों को आश्वस्त किया कि मध्यप्रदेश में उन्हें पारदर्शिता, सुविधाएं और तेज निर्णय प्रक्रिया मिलेगी।

दुबई में लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के चेयरमैन एम.ए. यूसुफ अली से मुलाकात में मुख्यमंत्री ने राज्य में फूड प्रोसेसिंग यूनिट और मल्टीपल हाइपरमार्केट खोलने का प्रस्ताव साझा किया, जिसे समूह ने सकारात्मक रूप से स्वीकार किया। इसी प्रकार, दुबई टेक्सटाइल सिटी के निवेशकों ने धार में प्रस्तावित पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क में निवेश की रुचि दिखाई।

इस यात्रा के दौरान करीब ₹1,000 करोड़ मूल्य की 'सस्टेनेबल सिटी' परियोजना का भी ऐलान हुआ, जो इंदौर के पास विकसित की जाएगी। इसके साथ ही, एनआरआई निवेशकों ने शिक्षा, पर्यटन, फार्मा और सौर ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश की सहमति भी दी।

स्पेन में मुख्यमंत्री ने लॉजिस्टिक और ग्रीन एनर्जी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर प्रदेश की सुविधाओं और नीति आधारित अवसरों को साझा किया।

मुख्यमंत्री ने इस दौरे को "मध्यप्रदेश के भविष्य की नींव रखने वाला कदम" बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सिर्फ दिखावा नहीं बल्कि ठोस निवेश सुनिश्चित करने का चरण है। उनका फोकस निवेश समझौतों को जमीन पर उतारने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने पर है।

यह दौरा मध्यप्रदेश के लिए बहुआयामी लाभकारी सिद्ध हुआ है और

आने वाले समय में यह राज्य को एक वैश्विक औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में मजबूत आधार बनेगा।

HDFC बैंक का FY27 तक उद्योग ऋण में तेज़ विस्तार का लक्ष्य, जमा वृद्धि में 14.6% हिस्सेदारी की उम्मीद

भोपाल: HDFC Bank ने वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) के लिए उद्योग से तेजी से अग्रिम वृद्धि का लक्ष्य रखा है। बैंक ने वित्त वर्ष 2025 की पहली तिमाही में 14.6% वृद्धिशील जमा हिस्सेदारी हासिल की, जो इसकी मजबूत स्थिति को दर्शाता है। प्रबंध निदेशक और सीईओ शशिधर जगदीशन ने मर्जर से प्राप्त तालमेल, कम क्रेडिट-जमा अनुपात और आक्रामक जमा रणनीति को इसका श्रेय दिया।

बैंक का सकल अग्रिम 5.4% साल-दर-साल और 4% तिमाही-दर-तिमाही बढ़कर ₹26.44 लाख करोड़ हो गया। अवधि अंत जमा 14.1% सालाना और 5.9% तिमाही-दर-तिमाही बढ़कर ₹27.15 लाख करोड़ रहा, जबकि औसत जमा 15.8% की वृद्धि के साथ ₹25.28 लाख करोड़ रहा। ये आंकड़े बैंक की जमा जुटाने की क्षमता को रेखांकित करते हैं।

जगदीशन ने कहा, "हमारा लक्ष्य ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करना है। FY27 में हम उद्योग की औसत वृद्धि दर को पार करेंगे।" बैंक ने डिजिटल बैंकिंग और ग्रामीण विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे ग्राहक आधार बढ़ा है।

विश्लेषकों का मानना है कि यह रणनीति HDFC Bank को बैंकिंग क्षेत्र में अग्रणी बनाए रखेगी, खासकर बढ़ती प्रतिस्पर्धा और डिजिटल मांग के बीच। 14.6% जमा हिस्सेदारी बैंक की निवेश और ऋण विस्तार की क्षमता को दर्शाती है। हालांकि, बढ़ती ब्याज दरें और वैश्विक अनिश्चितताएं चुनौतियां पेश कर सकती हैं।

HDFC Bank का मजबूत प्रदर्शन और रणनीति इसे इन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाती है। यह घोषणा निवेशकों में उत्साह जगाती है और FY27 में बैंक के प्रदर्शन पर नजर रहेगी।

Source: News18

Vision Invest Tech Private Limited | (+91)7389912025
ARN-10613 | visionadvisorymkt@gmail.com
POWERED BY
wealthy

केंद्र सरकार ने PM धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी

भोपाल: केंद्र सरकार ने बुधवार को प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना को मंजूरी दे दी, जो देश के 100 कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस योजना को 2025-26 से शुरू होने वाले छह वर्षों के लिए लागू किया जाएगा, और इसका उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है।

योजना का उद्देश्य और लाभ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को हरी झंडी दिखाई, जिसे नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरणा मिली है। यह योजना देश के उन 100 जिलों पर केंद्रित है, जहां कृषि उत्पादकता सबसे कम है। इसका मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है:

- **कृषि उत्पादकता में वृद्धि:** कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए आधुनिक तकनीकों और संसाधनों का उपयोग।
- **फसल विविधीकरण:** किसानों को विभिन्न फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करना, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो और जोखिम कम हो।
- **टिकाऊ कृषि प्रथाएँ:** पर्यावरण-अनुकूल खेती को बढ़ावा देना, जिसमें जैविक खेती और जल संरक्षण शामिल हैं।
- **भंडारण और सिंचाई सुविधाओं में सुधार:** बेहतर भंडारण और सिंचाई सुविधाएँ प्रदान करके फसल नुकसान को कम करना।
- **आसान ऋण सुविधा:** किसानों को सस्ते और सुलभ ऋण उपलब्ध कराना, ताकि वे अपनी खेती को और मजबूत कर सकें।

1.7 करोड़ किसानों को मिलेगा लाभ

केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना की घोषणा की थी, जिसमें कहा गया था कि यह योजना 1.7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ पहुँचाएगी। यह योजना राज्य सरकारों के सहयोग से लागू की जाएगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

पीएम मोदी का विजन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को अपनी उस सोच का हिस्सा बताया, जिसमें वे चाहते हैं कि दुनिया की हर रसोई में भारत के किसानों द्वारा उगाया गया कोई न कोई उत्पाद हो। उन्होंने कहा, "हमारा लक्ष्य उन जिलों को सशक्त बनाना है, जहां कृषि उत्पादकता कम है। यह योजना न केवल किसानों की आय बढ़ाएगी, बल्कि ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करेगी।"

योजना की विशेषताएँ

- **लक्षित जिले:** देश के 100 सबसे कम उत्पादकता वाले जिलों को चिह्नित किया गया है, जहां यह योजना लागू होगी।
- **समग्र विकास:** यह योजना कृषि के साथ-साथ ग्रामीण बुनियादी ढांचे, जैसे भंडारण और सिंचाई, को मजबूत करने पर ध्यान देगी।
- **किसान केंद्रित दृष्टिकोण:** किसानों को प्रशिक्षण, उन्नत बीज, और तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी।
- **स्थानीय रोजगार:** इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

भविष्य की दिशा: यह योजना भारत को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह योजना न केवल किसानों की आय बढ़ाएगी, बल्कि खाद्य सुरक्षा को भी मजबूत करेगी। साथ ही, यह ग्रामीण भारत में आर्थिक समृद्धि लाने में भी सहायक होगी।

केंद्र सरकार ने इस योजना के कार्यान्वयन के लिए व्यापक योजना बनाई है, जिसमें राज्य सरकारों, स्थानीय प्रशासन, और किसान

संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना के तहत पहले चरण में चयनित जिलों में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे, जिसके परिणामों के आधार पर इसे और विस्तार दिया जाएगा।

निष्कर्ष: प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना भारतीय कृषि क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू करने जा रही है। यह योजना न केवल कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों को समृद्ध करेगी, बल्कि भारत को वैश्विक कृषि बाजार में और मजबूत स्थिति प्रदान करेगी। यह कदम निश्चित रूप से किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा और ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।

Source: Navbharat Times

Sh. Pradeep Karambelkar
Founder & Editor

Dr. Irshad Ahmad Khan
Sub-Editor

Sh. Pushpendra Singh
Marketing Officer

CM Mohan Yadav's Relentless Push to Make Madhya Pradesh India's Next Industrial Hub

When Dr Mohan Yadav took oath as Chief Minister in December 2023, he promised to turn Madhya Pradesh (MP) into "the investors' second home." Eighteen months later, the evidence is visible in numbers, policies, and global outreach that have begun repositioning the heart of India as a magnet for industry and jobs.

1. A Pro Invest Policy Toolkit

At the MP Global Dialogue 2025 in Dubai this week, the Chief Minister unveiled a bouquet of 18 transparent industrial policies—from EVs and green hydrogen to data centres and logistics—that offer 100% CGST reimbursement, concessional land, capital subsidies and a single window clearance system. "Invest, and we won't leave any 'return gift' unfinished," he quipped to overseas Indians, underscoring the state's 24×7 investor hand holding mechanism.

2. Big Ticket Commitments at Home

On 12 July 2025 Indore hosted the Madhya Pradesh Growth Conclave, drawing ₹30,000 crore worth of proposals across industry, hospitality, real estate, education, renewables and IT—expected to create 15,000+ jobs. Dr Yadav also inaugurated and dedicated development works of ₹12,360 crore and announced ₹12,500 crore worth of urban packages, including fast tracked Bhopal & Indore Metros and 10 new smart city projects

.

3. Global Roadshows: From Dubai to Spain

The CM's 13–19 July Dubai–Spain tour is laser focused on export oriented manufacturing:

• UAE Minister of State for Foreign Trade Dr Thani Al Zeyoudi discussed opportunities under the India UAE CEPA; renewable power and tourism topped the agenda.
• MP pitched its sector specific parks—EV (Pithampur), Electronics (Bhopal), Pharma (Dewas), Engineering (Jabalpur), PM Mitra Textile Park (Dhar)—as ready made landing pads.
• In Dubai Textile City, Dr Yadav wooed apparel majors, reminding them that MP is India's largest producer of premium cotton.

The roadshow has already netted a ₹1,000 crore "Sustainable City" concept from Indore linked NRIs and multiple intent letters to co develop green energy projects, according to state officials.

4. Flagship Deals in the Pipeline

• Lulu Group International: Talks to set up a state of the art food & agro processing centre and hyper markets in Bhopal, Indore, Gwalior and Jabalpur, plus a fresh produce hub in the Indore Nimar belt.
• Textile Investments: Dubai investors have shown interest in partnering with the Dhar PM Mitra Park after the CM showcased a "showroom warehouse workshop" model inspired by Dubai Textile City.

5. Building the Hard Infrastructure

• 5 lakh km road network, two operational dry ports and upcoming multimodal logistics hubs in Jabalpur & Gwalior.
juggle a packed curriculum, making it difficult to add new subjects.
• 582 electric buses sanctioned under PM eBus Service for six major cities, underscoring MP's green mobility pivot.
• 10 lakh new urban homes and extensive AMRUT 2.0 water sewer upgrades to make industrial townships truly liveable.

is not just a reform—it is a necessity for a financially resilient future.

6. Jobs, Growth and the Inclusive Dividend

The state already ranks among India's fastest growing economies. Officials highlight that recent GIS and regional summits have fetched ₹30 lakh crore worth of MoUs on paper; what sets the current drive apart is the CM's insistence on time bound conversion and ground breaking ceremonies. Each big investment proposal is tagged to district wise employment targets and linked to skilling programmes at the upcoming Global Skill Park in Indore.
Outlook
From investor friendly policies and sector specific parks to relentless global courting, CM Mohan Yadav is orchestrating a multi pronged campaign to transform Madhya Pradesh into an industrial powerhouse. The early results—₹30,000 crore in domestic intents, foreign interest, and accelerated urban infrastructure—suggest the strategy is gaining traction. If execution keeps pace with ambition, MP could soon shed its land locked label and emerge as India's next big manufacturing and logistics node, fulfilling Dr Yadav's vision of an "MP for Business" that competes—not just with neighbouring states—but with the world.

Dr. Irshad Ahmod Khan
Sub-Editor

SAEL इंडस्ट्रीज ग्रेटर नोएडा में 8,200 करोड़ रुपये का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगी

भोपाल: भारत की अग्रणी नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी SAEL इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने ग्रेटर नोएडा में 8,200 करोड़ रुपये का निवेश करने की घोषणा की है, जहां वह एक एकीकृत सौर सेल और मॉड्यूल विनिर्माण संयंत्र स्थापित करेगी। यह परियोजना यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) के तहत संचालित होगी और SAEL सोलर P6 प्राइवेट लिमिटेड द्वारा कार्यान्वित की जाएगी। इस संयंत्र से कंपनी की कुल सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता 8.5 गीगावाट (GW) तक बढ़ जाएगी।

संयंत्र में 5 GW सौर सेल विनिर्माण इकाई और 5 GW सौर मॉड्यूल उत्पादन लाइन होगी। यह उन्नत टनल ऑक्साइड पासिवेटेड कॉन्टैक्ट (TOPCon) सौर सेल्स का उत्पादन करेगा, जो घरेलू मॉड्यूल असेंबली के लिए उपयोग में लाए जाएंगे। निर्माण कार्य इस वर्ष शुरू होने की उम्मीद है, जो भारत के स्थानीय सौर विनिर्माण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SAEL इंडस्ट्रीज के सह-संस्थापक और निदेशक सुखबीर सिंह अवला को इस परियोजना के लिए सहमति पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री ने कहा, "उत्तर प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ रहा है और इस तरह के 8,000 करोड़ रुपये के निवेश वाली परियोजनाएं हमारे लक्ष्यों को साकार करने में महत्वपूर्ण हैं। यह भविष्य है, और उत्तर प्रदेश इसके लिए तैयार है।"

सुखबीर सिंह अवला ने कहा, "यह संयंत्र हमारे विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने और भारत में सौर विनिर्माण के भविष्य में योगदान देने के लिए एक बड़ा कदम होगा। यह परियोजना राज्य की सौर नीति और राष्ट्रीय मिशनों जैसे आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत @2047 के अनुरूप है।" यह कदम सौर उपकरण आयात पर निर्भरता कम करने और घरेलू आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने में मदद करेगा।

SAEL की वर्तमान में 6.7 GW से अधिक सौर स्वतंत्र पावर उत्पादक (IPP) परिसंपत्तियां हैं, और यह परियोजना कंपनी के पिछड़े एकीकरण रणनीति को मजबूत करेगी। यह कदम भारत के सौर ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है।

Source: Mint

जियो ब्लैकरॉक 4 नए फंड लॉन्च करेगी: SEBI से अप्रूवल मिला

भोपाल: जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) से चार नए पैसिव फंड लॉन्च करने की मंजूरी मिल गई है। यह कदम निवेशकों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलता है और भारत के म्यूचुअल फंड उद्योग में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगा। इन फंड्स में तीन इक्विटी-ओरिएंटेड इंडेक्स फंड और एक डेट-ओरिएंटेड इंडेक्स फंड शामिल हैं, जो 500 रुपये की न्यूनतम राशि से निवेश की सुविधा प्रदान करेंगे।

नए फंड की जानकारी

जियो ब्लैकरॉक द्वारा लॉन्च किए जाने वाले चार फंड निम्नलिखित हैं:

• जियो ब्लैकरॉक निफ्टी मिडकैप 150 इंडेक्स फंड: यह फंड मिडकैप सेगमेंट में निवेशकों को अवसर प्रदान करेगा।

• जियो ब्लैकरॉक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड: यह फंड अगले 50 बड़े शेयरों पर केंद्रित होगा।

• जियो ब्लैकरॉक निफ्टी स्मॉलकैप 250 इंडेक्स फंड: यह स्मॉलकैप कंपनियों में निवेश का विकल्प देगा।

• जियो ब्लैकरॉक निफ्टी 8-13 ईयर G-Sec इंडेक्स फंड: यह दीर्घकालिक सरकारी प्रतिभूतियों पर आधारित होगा और कम जोखिम वाले निवेशकों के लिए उपयुक्त है।

ये सभी फंड केवल डायरेक्ट प्लान और ग्रोथ ऑप्शन में उपलब्ध होंगे, जिससे निवेश प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी।

जियो ब्लैकरॉक की यात्रा

जियो ब्लैकरॉक एक संयुक्त उद्यम है, जिसमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और अमेरिका की दिग्गज निवेश कंपनी ब्लैकरॉक की 50:50 की भागीदारी है। इस साल मई में SEBI ने कंपनी को म्यूचुअल फंड बिजनेस शुरू करने की मंजूरी दी थी। इसके बाद जियो ब्लैकरॉक ने तीन डेट फंड लॉन्च किए, जिनके जरिए 17,800 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जुटाई गई थी।

निवेशकों के लिए अवसर

इन फंड्स के लॉन्च से छोटे और मध्यम निवेशकों को बाजार में हिस्सेदारी लेने का मौका मिलेगा। 500 रुपये की न्यूनतम निवेश राशि के साथ, यह योजना आम लोगों के लिए वित्तीय सशक्तिकरण का एक साधन बन सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये फंड डायवर्सिफिकेशन और स्थिर रिटर्न की संभावना के साथ निवेशकों के पोर्टफोलियो को मजबूत करेंगे।

भविष्य की दृष्टि

जियो ब्लैकरॉक का लक्ष्य भारत को बचतकर्ताओं से निवेशकों की ओर ले जाना है। कंपनी की डिजिटल प्रौद्योगिकी और ब्लैकरॉक की वैश्विक विशेषज्ञता का मेल निवेश को आसान, सस्ता और सुरक्षित बनाने में मदद करेगा। आने वाले समय में कंपनी और नए उत्पाद लॉन्च करने की योजना बना रही है, जो भारतीय निवेशकों की विविध जरूरतों को पूरा करेगी।

इस मंजूरी के साथ जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड उद्योग में एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है, और यह कदम भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

Source: Business Standdard

IIFL Home Finance को AIIB से 100 मिलियन डॉलर का वित्तपोषण

भोपाल: IIFL Home Finance Limited (IIFL HFL), एक अग्रणी किफायती आवास वित्त कंपनी, ने एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (AIIB) से 100 मिलियन डॉलर (लगभग 858 करोड़ रुपये) का वित्तपोषण हासिल किया है। यह साझेदारी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) और निम्न-आय समूहों (LIG) के लिए किफायती आवास वित्त तक पहुंच बढ़ाने के साथ-साथ हरित भवन मानकों को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है।

IIFL HFL इस फंडिंग का उपयोग शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में EWS और LIG परिवारों को होम लोन प्रदान करने के लिए करेगा, ताकि वे अपने घर खरीद सकें या बना सकें। आपूर्ति पक्ष पर, कंपनी उन डेवलपर्स को वित्तपोषण देगी जो हरित प्रमाणन मानकों को अपनाने वाले किफायती आवास परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं, जिससे पर्यावरणीय प्रभाव कम होगा और स्थायित्व बढ़ेगा।

IIFL HFL के कार्यकारी निदेशक और सीईओ मोनू राला ने कहा, “AIIB से मिला यह वित्तपोषण देश भर में कम सेवा प्राप्त परिवारों के लिए गृहस्वामित्व के अवसरों का विस्तार करने की हमारी यात्रा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह हमें टिकाऊ और पर्यावरण के प्रति जागरूक आवास समाधान प्रदान करने में भी मदद करेगा।”

AIIB के वित्तीय संस्थान और फंड क्लाइंट विभाग के महानिदेशक ग्रेगरी लियू ने कहा, “यह निवेश AIIB की समावेशी और टिकाऊ बुनियादी ढांचे के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। IIFL HFL के साथ साझेदारी भारत के हरित भवन एजेंडे को आगे बढ़ाने और निम्न-आय परिवारों के लिए आवास अंतर को कम करने में मदद करेगी।”

यह निवेश भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं और प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U 2.0) के अनुरूप है, जो शहरी आवास की कमी को दूर करने का लक्ष्य रखती है। IIFL HFL, 18 राज्यों में 376 शाखाओं के नेटवर्क के साथ, टियर 1 शहरों के उपनगरों और टियर 2 से टियर 4 शहरों पर केंद्रित है।

Source: Business Standard

Tesla Partners with Liberty General and ACKO for EV Insurance in India

Bhopal: Tesla’s entry into India has taken a significant step forward with the opening of its first showroom in Mumbai’s Maker Maxity Mall at Bandra Kurla Complex. Alongside this milestone, Tesla has partnered with Liberty General Insurance Ltd. and ACKO General Insurance to provide tailored insurance solutions for its electric vehicles (EVs), marking a pivotal moment for India’s EV ecosystem.

Tesla’s Model Y, priced at approximately ₹60 lakh for the rear-wheel-drive variant and ₹68 lakh for the long-range variant, will be supported by specialized insurance plans designed for EV owners. Liberty General Insurance and ACKO, named Tesla’s preferred insurance partners, aim to enhance the ownership experience with innovative coverage options.

Liberty General: Comprehensive EV Protection

Liberty General Insurance offers advanced EV insurance, including battery protection and comprehensive roadside assistance. Parag Ved, CEO & Whole-Time Director, stated, “Tesla’s arrival marks a new era of mobility. We’re honored to be a preferred insurer, inspiring EV adoption with smart, seamless protection.” Liberty’s “Complete Assistance” package includes on-the-spot charging, flatbed towing, and travel support, ensuring Tesla owners’ convenience and peace of mind.

ACKO: Digital-First Insurance

ACKO, known for its digital-first approach, integrates insurance into the car-buying process, offering a fully digital experience from quotes to claims. Animesh Das, Managing Director & CEO, said, “Tesla redefines cars; we’re redefining insurance to be simple and responsive.” ACKO’s technology-driven solutions align withesla’s vision, streamlining ownership

T and supporting EV adoption in India.

Transforming India’s EV Landscape

Tesla’s entry intensifies competition in India’s growing EV market, alongside players like Mahindra, Tata Motors, and BYD. The partnerships with Liberty and ACKO underscore Tesla’s commitment to a holistic ownership experience, addressing insurance and infrastructure needs. Tesla also plans to introduce V4 Superchargers and expand charging infrastructure. Model Y deliveries are set to begin in Q3 2025 for the standard variant, with the long-range variant following in Q4.

A Sustainable Future

By combining innovative vehicles with tailored insurance, Tesla, Liberty General, and ACKO are setting a new standard for EV ownership in India. With plans for showrooms in Delhi and Gurugram, Tesla’s journey promises to reshape mobility with sustainability and customer-centric services.

Sources: Business Today

Kia India Names Atul Sood as New SVP of Sales & Marketing

Bhopal: Kia India has announced the appointment of Atul Sood as its Senior Vice President of Sales & Marketing, effective July 11, 2025. Sood, a seasoned automotive industry veteran with nearly three decades of experience, steps into the role previously held by Hardeep Singh Brar, who has transitioned to the position of President and CEO at BMW Group India.
Sood joins Kia India from Toyota Mobility Solutions and Services India (TMSS), where he served as President and Director. His tenure at Toyota included significant contributions, such as spearheading the launch of Toyota-certified pre-owned car outlets across India. Prior to TMSS, Sood held leadership roles at Toyota Kirloskar and Toyota Motor Asia Pacific, where he honed his expertise in business growth, dealer network expansion, and customer-centric initiatives.
In his new role, Sood will report to Joonsu Cho, Chief Sales Officer at Kia India, and is expected to drive the company's next phase of growth in the highly competitive Indian automotive market. Kia India, known for its innovative and customer-focused approach under its "Movement That Inspires" brand philosophy, currently operates 744 touchpoints across 329 cities. Sood's appointment aligns with the company's ambitions to further strengthen its nationwide presence and enhance its market share.
Expressing enthusiasm about his new role, Sood stated, "I am excited to join Kia India at such a dynamic time in its evolution. Kia has established itself as a forward-thinking and customer-focused brand, and its commitment to innovation and customer delight resonates strongly with me. I look forward to working with the team to deliver exceptional value and drive sustainable growth across the country."
Kia India's recent milestones include the launch of models like the updated Seltos, Sonet, the three-row Carens, the premium electric vehicle EV6, the new-generation Carnival, and the recently unveiled Syros and Carens Clavis. The company is alsoset to introduce the Carens Clavis EV

July 15, 2025, further bolstering its portfolio in the Indian market.
Industry analysts view Sood's appointment as a strategic move to leverage his extensive experience to navigate challenges such as rising raw material costs and declining sales of models like the Sonet and Seltos, while capitalizing on the success of the Carens, which emerged as Kia's top-selling model in June 2025.
As Kia India continues to expand its footprint and innovate, Sood's leadership is poised to play a pivotal role in shaping the brand's future in one of the world's most dynamic automotive markets.

Source: Economic Times

JLR to Launch Tamil Nadu Assembly Plant in 2026, Tata Motors Postpones Avinya EV Debut

Bhopal: Jaguar Land Rover (JLR), the luxury vehicle arm of Tata Motors, is set to commence vehicle assembly at a new facility in Ranipet, Tamil Nadu, by early 2026, marking a significant step in expanding its manufacturing footprint in India. Concurrently, Tata Motors has announced a delay in the launch of its premium Avinya electric vehicle (EV) range, now scheduled for 2027, due to engineering and supply chain challenges.
The Ranipet plant, backed by a ₹9,000 crore investment over five years, will initially focus on assembling the Range Rover Evoque and Velar SUVs from completely knocked-down (CKD) kits, with a starting capacity of 30,000 units annually. Tata Motors plans to gradually shift JLR's existing CKD operations from its Pune facility to Ranipet, aiming for a full capacity of over 250,000 units within five to seven years. The facility will also support the production of next-generation vehicles for both JLR and Tata Motors, including future electric models. "This move provides a scalable, future-ready base for JLR's expansion in India," said PB Balaji, Group CFO of Tata Motors, emphasizing the plant's role in enhancing ogistical efficiencies logistical efficiencies and leveraging the anticipated India-UK Free Trade Agreement to streamline costs.
The Tamil Nadu facility was initially planned to produce JLR's electric vehicles based on the Electrified Modular Architecture (EMA) platform, alongside Tata's Avinya EVs. However, JLR recently shelved its EV production plans at Ranipet due to challenges in balancing cost and quality with locally sourced components, impacting the Avinya timeline. Tata Motors had aimed to launch the first Avinya model, codenamed P1, in 2025, but the timeline has been pushed to 2027 as the company reworks its design and supply chain strategy. "As part of our rigorous product development process, we continuously evaluate design, supply chain readiness, and unit economics," Tata Motors stated.
The Avinya range, intended to position Tata Motors in the premium EV segment without overt Tata branding, was set to leverage JLR's EMA platform for models like the P1, a coupe-crossover, and P4, a lifestyle SUVThe delay reflects broader challenges in India's EV market, including competition from players like JSW MG Motor and Mahindra, and policy distortionsfavoring hybrids over EVs, as noted by Shailesh Chandra, MD of Tata Motors Passenger Vehicles.
JLR's move to Tamil Nadu aligns with its strategy to counter global trade headwinds, including 27.5% US import tariffs, through localized production and cost-cutting measures. The company, which reported a 10.7% decline in wholesale units for Q1 FY26, is focusing on high-margin models like the Range Rover, Range Rover Sport, and Defender, which comprised 77.2% of its sales. Despite the EV setback, the Ranipet plant is expected to bolster JLR's presence in India, where it recorded a 40% sales surge last year, overtaking Audi India.
As Tata Motors navigates these challenges, the Ranipet facility remains a cornerstone of its long-term vision to strengthen both JLR's luxury offerings and its own EV ambitions in India's rapidly evolving automotive market.

Source: Economic Times

मैरिको का 2030 तक 20,000 करोड़ रुपये की FMCG कंपनी बनने का लक्ष्य

भोपाल: प्रमुख FMCG कंपनी मैरिको ने 2030 तक अपनी आय को दोगुना कर 20,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। कंपनी के चेयरमैन हर्ष मारीवाला ने कहा कि यह लक्ष्य नवाचार, ब्रांड निर्माण और परिचालन उत्कृष्टता पर आधारित है। मैरिको, जो पैराशूट, सफोला और लिवॉन जैसे लोकप्रिय ब्रांडों के लिए जानी जाती है, ने वित्त वर्ष 2025 में 10,000 करोड़ रुपये की आय का आंकड़ा पार किया।

कंपनी अब अपने खाद्य और प्रीमियम पर्सनल केयर सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित कर रही है। सफोला ब्रांड के तहत खाद्य व्यवसाय FY20 से पांच गुना बढ़कर FY25 में 900 करोड़ रुपये को पार कर गया। प्रीमियमपर्सनल केयर, जिसमें बियर्डो, जस्ट हर्ब्स और प्लिक्स जैसे ब्रांड शामिल हैं, ने भी मजबूत वृद्धि दिखाई। इन दोनों सेगमेंट ने FY25 में भारत के राजस्व का 22% योगदान दिया, जिसका संयुक्त वार्षिक राजस्व 2,000 करोड़ रुपये रहा। मैरिको को उम्मीद है कि यह हिस्सेदारी FY27 तक 25% तक बढ़ जाएगी।

प्रबंध निदेशक और सीईओ सौगत गुप्ता ने कहा, "हमारा उद्देश्य उपभोक्ता-केंद्रित पोर्टफोलियो को मजबूत करना है, जो विविध और गतिशील जनसांख्यिकी की आकांक्षाओं को पूरा करे।" कंपनी का डिजिटल-फर्स्ट पोर्टफोलियो FY25 में 750 करोड़ रुपये की वार्षिक राजस्व दर के साथ समाप्त हुआ और FY27 तक यह FY24 की तुलना में 2.5 गुना बढ़ने की उम्मीद है।

मैरिको ने FY24 और FY25 में सकल मार्जिन को 1,000 आधार अंकों तक बढ़ाया है और मध्यम अवधि में क्रमिक मार्जिन विस्तार की उम्मीद करती है। कंपनी की रणनीति में डिजिटल-फर्स्ट ब्रांड, नवाचार पर जोर है, जिससे यह वैश्विक स्तर पर एक प्रशंसनीय डिजिटल FMCG कंपनी बनने की दिशा में अग्रसर है।

Source: Business Standard

भारत के नए तांबा आयात नियम आपूर्ति संकट को जन्म दे सकते हैं, ट्रेड बॉडी ने चेतावनी दी

भोपाल: भारत के नए तांबा आयात नियमों को लेकर चिंता बढ़ गई है, क्योंकि बॉम्बे मेटल एक्सचेंज (BME) ने चेतावनी दी है कि ये नियम देश में तांबे की आपूर्ति में संकट पैदा कर सकते हैं। दिसंबर 2024 में लागू किए गए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (QCO) के तहत तांबे की कैथोड आयात पर सख्त मानकों को लागू किया गया है, जिससे विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर अनुपालन का बोझ बढ़ गया है। BME का दावा है कि इससे आयात में कमी आई है, जो डाउनस्ट्रीम उद्योगों के लिए गंभीर चुनौती बन सकता है।

BME के अनुसार, ये नियम विदेशी आपूर्तिकर्ताओं के लिए "महंगा और अनावश्यक अनुपालन बोझ" लाए हैं, जिसके कारण जापान जैसे प्रमुख आपूर्तिकर्ता देशों से आयात प्रभावित हो रहा है। जापान भारत के परिष्कृत तांबे के आयात का लगभग दो-तिहाई हिस्सा प्रदान करता है, इसके बाद तंजानिया और मोजाम्बिक हैं। BME का कहना है कि जापानी आपूर्तिकर्ता इन नियमों के कारण भारतीय बाजार से हट सकते हैं। हालांकि, जापानी ट्रेडिंग हाउस मारुबेनी ने दावा किया है कि आपूर्ति में कोई विशेष समस्या नहीं है।

सरकार ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा है कि QCO से कोई एकाधिकार नहीं बनेगा और आपूर्ति में कोई कमी नहीं होगी। वाणिज्य मंत्रालय के एक सूत्र ने कहा, "दिसंबर-जनवरी में आयात में कमी पुरानी जानकारी है, क्योंकि कंपनियों ने अक्टूबर-नवंबर में बड़ी मात्रा में स्टॉक जमा किया था।" सरकार ने बताया कि 10 विदेशी और 5 घरेलू आपूर्तिकर्ता प्रमाणित हैं, जिसमें जापान के 7 आपूर्तिकर्ता शामिल हैं। तांबा 2023 में भारत द्वारा चिह्नित 30 महत्वपूर्ण खनिजों में से एक है, और 2030 तक इसकी मांग दोगुनी होने की उम्मीद है। प्रमुख घरेलू आपूर्तिकर्ता हिंदाल्को इंडस्ट्रीज और हिंदुस्तान कॉपर हैं। इस बीच, ट्रेड बॉडीज ने बॉम्बे हाई कोर्ट में इस नियम को चुनौती दी है, यह दावा करते हुए कि यह घरेलू आपूर्तिकर्ताओं के एकाधिकार को बढ़ावा दे सकता है। मामला अभी विचाराधीन है, और इसका परिणाम भारतीय तांबा उद्योग के भविष्य को प्रभावित करेगा।

Source: Business Standard

हिंदुस्तान जिंक ने राजस्थान में पोटाश ब्लॉक हासिल किया

भोपाल: हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल) ने हाल ही में राजस्थान में एक महत्वपूर्ण पोटाश ब्लॉक हासिल किया है, जो भारत के खनन क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। खान मंत्रालय द्वारा आयोजित ई-नीलामी के पांचवें चरण के तहत यह ब्लॉक कंपनी को आवंटित किया गया है। यह ब्लॉक हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और इसके क्षेत्रफल में 1,841.25 हेक्टेयर शामिल है। यह कदम भारत की पोटाश आयात पर निर्भरता को कम करने और खनिज सुरक्षा के लक्ष्यों को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है।

पोटाश एक प्रमुख खनिज है, जो उर्वरक उद्योग में एनपीके उर्वरकों के उत्पादन के लिए उपयोगी है। वर्तमान में, भारत अपनी पोटाश आवश्यकताओं का 100% आयात करता है, जो मुख्य रूप से कनाडा, रूस, बेलारूस और जॉर्डन जैसे देशों से होता है। इस नई पहल से घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे आयात लागत में कमी आएगी और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।

हिंदुस्तान जिंक के सीईओ अरुण मिश्रा ने कहा, "पहली बार भारत में पोटाश ब्लॉक हासिल करना हमारी रणनीतिक खनिज खोज क्षमता का प्रमाण है। हम महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और राष्ट्र की खनिज सुरक्षा के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।" कंपनी पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा एकीकृत जिंक उत्पादक और शीर्ष पांच चांदी उत्पादकों में से एक है, जो 40 से अधिक देशों को आपूर्ति करती है।

यह कदम न केवल कंपनी के लिए बल्कि भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए भी महत्वपूर्ण है। हालांकि, खनन शुरू होने में समय लगेगा, क्योंकि ब्लॉक अभी शुरुआती खोज (जी3) स्तर पर है।

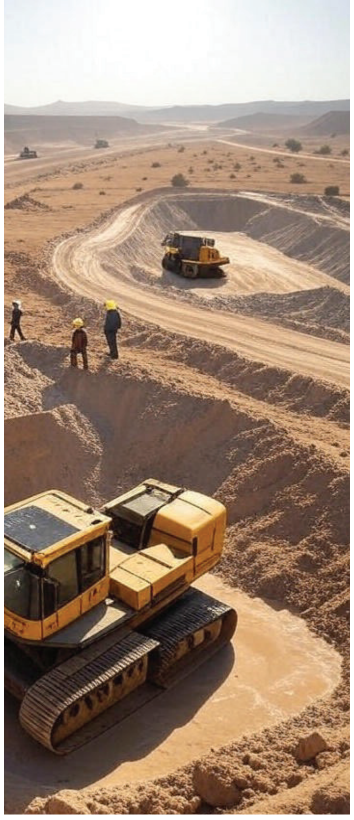

Source: Money Control

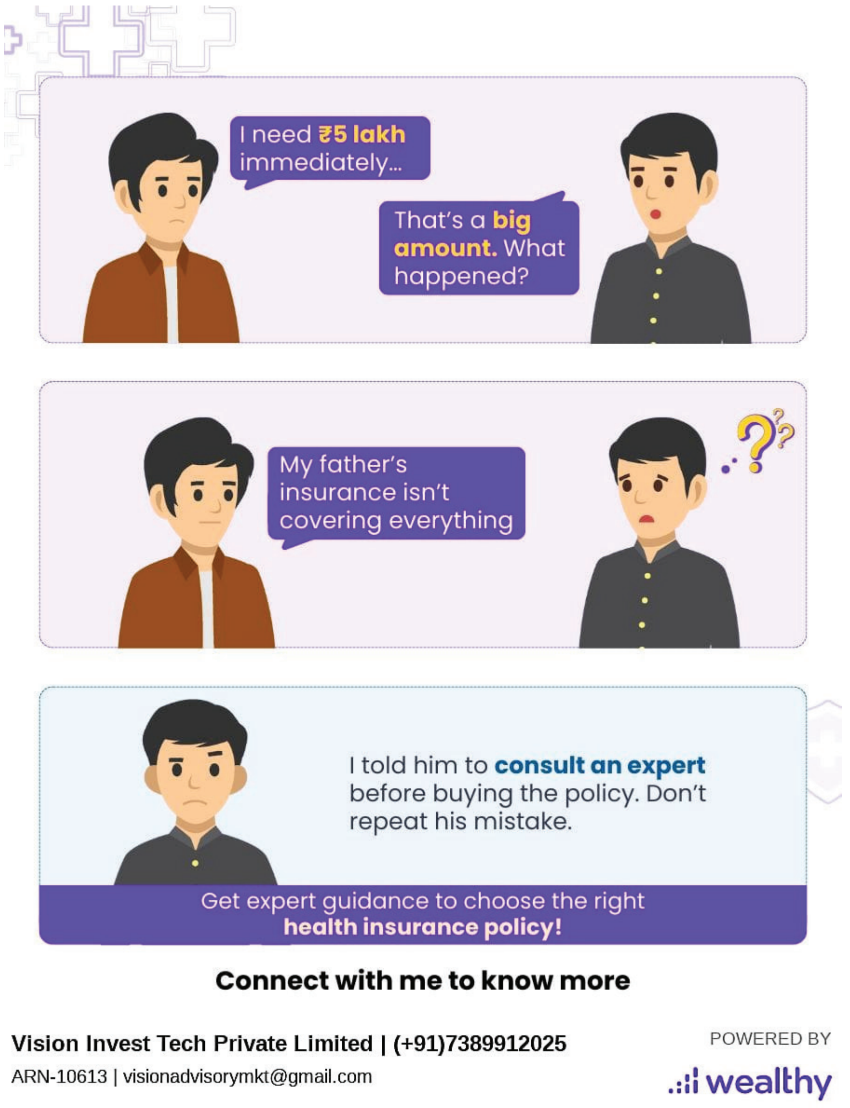

India's Warehousing Sector Embraces Sustainability to Meet MNC Demands

corporations (MNCs) increasingly prioritize sustainable logistics spaces. Driven by global environmental mandates and cost efficiencies, this shift is reshaping the $15 billion industry, projected to grow at a 10% CAGR through 2030.

MNCs like Amazon, Walmart, and Unilever are demanding warehouses with eco-friendly features, such as solar panels, rainwater harvesting, and energy-efficient designs. These align with their net-zero goals and ESG (Environmental, Social, Governance) commitments. For instance, Amazon's fulfillment centers in India now incorporate solar rooftops, reducing carbon footprints by 20-30% per facility. Similarly, DHL has introduced green logistics hubs with electric vehicle (EV) charging stations to support sustainable last-mile delivery.

Developers are responding swiftly. Prologis and ESR India are integrating LEED-certified designs, using sustainable materials like recycled steel and low-carbon concrete. Warehouses in prime logistics hubs like Bengaluru, Mumbai, and Chennai are adopting IoT-enabled energy management systems to optimize power usage. These upgrades not only attract MNCs but also reduce operational costs by 15-20% over time, despite higher initial investments.

Government policies are fuelling this trend. The National Logistics Policy (2022) emphasizes sustainable infrastructure, offering incentives for green certifications. Tax breaks and subsidies for solar installations have encouraged developers to retrofit older warehouses. Additionally, India's commitment to net-zero by 2070 has spurred investments in green logistics, with $2 billionwith $2 billion allocated to sustainable warehousing projects in 2024 alone.

However, challenges remain. High upfront costs and a lack of skilled labor for green construction slow adoption. Yet, as MNCs tie contracts to sustainability metrics, developers are compelled to innovate. India's warehousing sector is poised to become a global model for green logistics, balancing profitability with environmental responsibility.

Source: Economic Times

Sun Pharma Introduces Leqselvi in US Following Patent Resolution

Bhopal: Sun Pharmaceutical Industries Ltd., India's leading drugmaker by revenue, has launched its groundbreaking hair loss treatment, Leqselvi (deuruxolitinib), in the US market after resolving a prolonged patent dispute with Incyte Corporation. The announcement, made on Monday, marks a significant milestone for the Mumbai-based company, expanding its dermatology portfolio with an FDA-approved solution for severe alopecia areata, an autoimmune condition causing significant hair loss.

Leqselvi, approved by the US Food and Drug Administration in July 2024, faced delays due to a patent infringement lawsuit filed by Incyte, which alleged that the drug violated its existing patents. The US District Court of New Jersey initially granted a preliminary injunction in November 2024, halting the launch.

However, a favorable ruling from the US Court of Appeals for the Federal Circuit in April 2025 lifted the injunction, paving the way for negotiations. The recent settlement, finalized with an upfront payment and ongoing royalties to Incyte, includes a limited, non-exclusive license to relevant US patents, allowing Sun Pharma to proceed without further legal hurdles.

The 8 mg Leqselvi tablets are now available across the US, offering hope to adults with severe alopecia areata. Clinical trials, including THRIVE-AA1 and THRIVE-AA2, demonstrated that nearly one-third of patients achieved near-complete hair regrowth within 24 weeks. Richard Ascroft, CEO of Sun Pharma North America, hailed the launch as a "key milestone" and an "important advancement" for affected communities.

Analysts are optimistic, with estimates suggesting Leqselvi could generate $200–400 million in sales by FY30, potentially reaching a peak of $900 million. This launch strengthens Sun Pharma's position in the competitive US market, despite challenges like pricing pressure. The settlement ends a year-long legal battle, with both companies agreeing to dismiss the litigation in the US District Court for the District of New Jersey and release all related claims.

Sun Pharma's success with Leqselvi, acquired via a $576 million deal with Concert Pharma in 2023, underscores its growing influence in specialty pharmaceuticals, offering a new treatment option for a condition impacting millions globally.

Source: Business Standard

WEEKLY STOCK PIVOT LEVEL

Anil Bhardwaj
Technical Head
anil.stockcare@gmail.com

All level indicated above are based on future prices PP: Pivot Point: This is TRIGGER POINT for buy/sell Based on the price range of the previous Month, R1: Resistance one: 1st Resistance over PP; R2: resistance Two: 2nd Resistance over R1; S1: Support one: 1st support after PP; S2: Support Two: 2nd support after S1

- As per tool, trader should take Buy position just above pp and keep the stop loss of PP and 1st target would be R1
- If R1 is crossed then R2 becomes the next target with the stop loss at R1
- If R2 is crossed then R3 becomes the next target with the stop loss at R2.
- Similarly, if price goes below PP the trader should SELL price below PP as stop loss and the first target would be S1,
- If S1 is crossed then S2 becomes the next target with the stop loss at S1,
- If S2 is crossed then S3 becomes the next target with the stop loss at S2.

Stock name	closing	R3	R2	R1	PP	S1	S2	S3
NIFTY	24968	25510	25382	25175	25047	24840	24712	24505
BANK NIFTY	56283	58037	57656	56969	56588	55901	55520	54833
FINNIFTY	26556	27368	27189	26872	26693	26376	26197	25880
MIDCAP	13171	13728	13553	13352	13187	12995	12821	12630
ACC	1973	2032	2015	1994	1977	1956	1939	1918
AXISBANK	1099	1246	1213	1156	1123	1066	1033	976
ABCAPITAL	264	279	276	270	267	261	258	252
BHARTIARTL	1902	1987	1966	1934	1913	1881	1860	1828
BHEL	251	267	263	257	253	247	243	237
BIOCON	399	450	428	413	391	376	354	339
CDSL	1699	1801	1768	1733	1700	1665	1632	1597
DATAPATTERN	2754	3067	3000	2877	2810	2687	2620	2497
ESCORTS	3410	3696	3578	3494	3376	3292	3174	3090
EICHERMOTOR	5621	5856	5769	5695	5608	5534	5447	5373
FEDERAL BANK	213	226	220	216	211	207	202	198
GRINFRAPOJECT	1277	1373	1333	1305	1265	1237	1197	1169
HDFCBANK	1956	2066	2043	1999	1976	1932	1909	1865
HCLTECH	1549	1726	1683	1616	1573	1506	1463	1396
HINDUNILVR	2488	2571	2552	2520	2501	2469	2450	2418
HAL	4651	5128	5030	4840	4742	4552	4454	4264
HYUNDAI	2120	2234	2199	2159	2124	2084	2049	2009
IOC	150	156	154	152	150	148	146	144
ICICIBANK	1427	1464	1449	1438	1423	1412	1397	1386
INFY	1588	1663	1637	1612	1586	1561	1535	1510
ITC	423	436	431	427	422	418	413	409
KOTAKBNK	2135	2303	2268	2201	2166	2099	2064	1997
LICHOUSING	628	695	671	649	625	603	579	557
LT	3469	3626	3587	3528	3489	3430	3391	3332
LUPIN	1930	2036	1998	1964	1926	1892	1854	1820
MARUTI	12423	12820	12719	12571	12470	12322	12221	12073
M&M	3199	3480	3366	3282	3168	3084	2970	2886
MGL	1509	1618	1577	1543	1502	1468	1427	1393
MAZGAONDOC	2980	3271	3210	3095	3034	2919	2858	2743
PFC	419	442	437	428	423	414	409	400
RECLTD	400	414	409	404	400	395	391	386
RELIANCE	1477	1526	1513	1495	1482	1464	1451	1433
SBIN	823	874	858	840	824	806	790	772
SUNPHARMA	1694	1778	1754	1724	1700	1670	1646	1616
SHRIRAMFINANCE	645	716	702	673	659	630	616	587
TITAN	3398	3553	3500	3449	3396	3345	3292	3241
TCS	3190	3320	3293	3241	3214	3162	3135	3083
TATAMOTORS	680	702	694	687	679	672	664	657
UPL	686	758	728	707	677	656	626	605
VALIENT	400	436	427	413	404	390	381	367
WIPRO	267	293	282	274	263	255	244	236

Tata Chairman Launches 1.25 billion Pound Green Steel Initiative in UK

Tata Group Chairman Natarajan Chandrasekaran launched a £1.25 billion green steel project at Port Talbot, marking a pivotal shift to sustainable steelmaking in the UK. The ceremony, attended by UK government ministers and Tata Steel executives, including CEO T V Narendran, highlights a commitment to cut carbon emissions by 90%. The project replaces traditional blast furnaces with an Electric Arc Furnace (EAF) using local scrap steel, backed by £500 million from the UK Government. This major investment, the largest in UK steelmaking in decades, aims to preserve 5,000 jobs at Tata Steel UK. Set for completion by late 2027, the EAF is projected to reduce Port Talbot's carbon emissions by 5 million tonnes annually, totaling 50 million tonnes over a decade. Chandrasekaran called it "a new era for sustainable manufacturing," while Business Secretary Jonathan Reynolds noted it as "our Industrial Strategy in action, securing thousands of jobs." Wales Secretary Jo Stevens emphasized the £500 million investment, plus £80 million for workers and communities, ensuring steelmaking's future. Led by contractor Sir Robert McAlpine, the project supports Tata Steel's net-zero goal by 2045 and strengthens UK industrial decarbonization, positioning Port Talbot as a global leader in green steel production, balancing economic stability and environmental responsibility.

Disclaimer: This content is for educational purposes only. Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.Investments are subject to market risks. Please conduct your own research or consult a qualified financial advisor before making any investment decisions.

प्रकाशक एवं मुद्रक: प्रदीप कारबेलकर, सी-101, नेहरू नगर स्वत्वाधिकार द इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज प्रा.लि., इ-4, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, मध्य प्रदेश 462016, से प्रकाशित एवं DigitalLok, सागर हाई स्ट्रीट, अयोध्या बायपास रोड, डी मार्ट के पास, भोपाल, (म.प्र.) - 462010। संपादक: प्रदीप कारबेलकर (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)। फोन: +9198262 23075 वेबसाइट: www.investmentavenues.in